Dr. Pushpa Chauhan
Professor, Deptt of Economics
Vaishali Mahila College, Hajipur

Part-2, Paper-IV
27/07/2020

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास
Growth of Public Sector in India Since 1948

सार्वजनिक क्षेत्र से अर्थ ऐसी संस्थाओं से है जिनका स्वामित्व, प्रबन्ध एवं नियन्त्रण केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकार या किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा किया जाता है। भारत में व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रियाओं में राजकीय हस्तक्षेप नवीन विचारधारा नहीं है। प्राचीन भारत में आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप दो रूप में प्रचलित था (1) उद्योगों का सरकारी स्वामित्व (2) सरकार द्वारा उनका नियमन।

स्वतन्त्रता से पूर्व ब्रिटीश काल में लौह उद्योगों का महत्वपूर्ण विकास एवं विस्तार नहीं हुआ। इस काल में जो कुछ औद्योगिक विकास हुआ वह केवल प्रशासनिक आवश्यकता तथा जन चेतना का ही परिणाम था।

भारत में केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों का अस्तित्व स्वतन्त्रता के पूर्व भी था परन्तु कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था जैसे - सैनिक साज-सज्जा उत्पादन, रेल, डाक व तार, पोर्ट-ट्रस्ट, सिंचाई व प्रसारण तथा कुछ सामग्री तक ही सीमित था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने, तीव्र गति से औद्योगीकरण करने, समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करने और धन वितरण की असमानता को कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र का विकास एवं विस्तार आवश्यक समझा गया।

1948 में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रगतिशील महत्व को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1948 के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव

पेपर मिल, बंगलौर में एच. एम. टी. फैक्टरी, कोयली में तेल शोधक कारखाना एवं कोटा में प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेण्ट फैक्टरी खोली गयी।

चौथी एवं पांचवी योजनाओं मे पुरानी इकाइयों का विस्तार किया गया।

नियोजन काल मे केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों का विकास निम्न प्रकार हुआ है

वर्ष	उपक्रमों की संख्या	कुल विनियोजित पूंजी
1950-51	05	29 करोड़
1960-61	47	948 " cr
1973-74	122	6,237 cr
1984-85	215	42,673 cr
1996-97	238	2,01,500 cr
2009-10	249	5,79,920 cr

वस्तुतः आज भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, खान एवं खनन, कृषि, परिवहन, संचार, व्यापार, वित्त, बीमा, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में सार्वजनिक उद्यम स्थापित किए जा चुके है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का औचित्य
Rationale of The Expansion of Public sector in India.

भारत जैसे विकासशील देश जिसका मुख्य उद्देश्य तीव्र गति से आर्थिक तथा औद्योगिक विकास करना है। जिसके लिए विशाल पूंजी के विनियोग की

contd.

में तत्कालीन उद्योग मंत्री डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था "उद्योग के विकास में राज्य को उत्तरोत्तर अधिक सक्रिय भाग लेना चाहिए।"

भारत में स्वतन्त्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया तथा समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य निर्धारित किया गया। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना से नियोजित ढंग से आर्थिक विकास की प्रक्रिया को अपनाया गया।

देश को आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश को कृषि प्रधान देश से उद्योग प्रधान देश बनाना जाए। इसके लिए अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप तथा उत्तरदायित्व का बढ़ना आवश्यक माना गया। 1948 के बाद 1956, 1970, 1973, 1977 एवं 1980 में घोषित औद्योगिक नीतियों में सरकारी क्षेत्र का और विस्तार किया गया। विशेष रूप से आयोजना काल सार्वजनिक क्षेत्र को भारी दायित्व सौंपा गया

1948 एवं 1956 की औद्योगिक नीतियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, सिन्दरी फर्टिलाइजर हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स, चितरंजन लोकोमोटिव्स की गुरुआत की गयी

1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय योजनाकाल में दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई में इस्पात के कारखाने, आयल इण्डिया, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, फर्टिलाइजर कारपोरेशन की नींव रखी गयी। 1956 में भारतीय जीवन बीमा एवं राज्य व्यापार निगम स्थापित किए गए।

तृतीय योजनाकाल में विशाखापत्तनम में सिन्दरी

Dr Pushpa Chauhan
Professor, Deptt. of Economics
Vaishali Mahila College Hajipur

आवश्यकता होती है जिसे निजी क्षेत्र पूरा करने में असमर्थ होता है। अतः भारत में निम्न कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार अपरिहार्य (inevitable) माना जाता है।

1. समाजवादी समाज की स्थापना - भारत में समाजवादी समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया "समाजवादी ढंग के समाज को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपनाने और नियोजित एवं तीव्र विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आधारभूत एवं सामरिक महत्व के सभी उद्योग तथा जनोपयोगी सेवाएँ सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाएं। इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के विकास से समाजवादी समाज की स्थापना में सहयोग मिलेगा।

2. आर्थिक एवं औद्योगिक संरचना का निर्माण - स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश की औद्योगिक संरचना काफी कमजोर थी। आधारभूत संरचना का अभाव, आधारभूत उद्योगों का अभाव, उन्नत टेक्नोलोजी, मशीनों का अभाव था। तीव्र आर्थिक विकास के लिए इन कमियों को दूर करना था जो सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से ही सम्भव था। इसलिए स्वतन्त्रता के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया गया।

3. क्षेत्रीय सन्तुलित विकास - सन्तुलित आर्थिक विकास का विचार सार्वजनिक क्षेत्र की देन है। पूँजीपति या उद्योगपति उन्हीं स्थानों पर कारखाना, उद्योग की स्थापना करते हैं जहाँ प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं तथा लाभ की सम्भावना ज्यादा रहती है। जिससे कुछ क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। अतः सरकार का

शामिल होता है कि उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करे जो पिछड़े हुए हैं ~~जिनमें~~ जिनमें स्थानीय साधन पर्याप्त नहीं है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही पिछड़े हुए क्षेत्रों में व्यय विनियोग किया जाता है इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है।

4. द्रुतगामी आर्थिक विकास – भारत का लक्ष्य तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है जिसके लिए ऊँची वृद्धि दर अपेक्षित है। उच्च विकास दर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारी निवेश एवं जोखिम की आवश्यकता होती है जो निजी क्षेत्र पूरा नहीं कर सकता। इसलिए सरकारी क्षेत्र का विस्तार विकास एवं विस्तार किया गया।

5. आर्थिक विषमताओं पर रोक – भारत में पूंजी निर्माण का अभाव है साथ साथ आय एवं सम्पत्ति का असमान वितरण है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद धन के ~~आय~~ वितरण की असमानता और बढ़ गयी है इस आर्थिक विषमता को सार्वजनिक क्षेत्र के विकास एवं विस्तार से ही कम किया जा सकता है क्योंकि सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ कुछ हाथों में केन्द्रित न होकर पूरे समाज में वितरित होता है। जिससे आय की विषमताएँ घटती हैं।
धन का वितरण समान होने पर बचत करने की शक्ति और पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

6. निजी क्षेत्र की बुराइयाँ – निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है, इनके द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है यानि आवश्यक मजदूरी नहीं दी

जाती, वस्तु की कृत्रिम कमी पैदा करना, दुर्लभ पदार्थों को अधिकाधिक लाभ पर बेचना इससे समाज को हानि होती है, इन सब कमियों को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार किया गया।

7. सार्वजनिक क्षेत्र की अपरिहार्यता – सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का एक प्रमुख उद्देश्य उन महत्वपूर्ण क्रियाओं, क्षेत्रों, उद्योगों का संचालन करना है जिसे निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए तो राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है इसलिए निम्न उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार एक अपरिहार्य आवश्यकता है

(a) सामरिक महत्व के उद्योग या सुरक्षात्मक उद्योग

(b) वे उद्योग जिनमें भारी विनियोग की आवश्यकता है।

(c) लम्बी परिपाक अवधि वाले उद्योग, जिनमें [illegible] प्रतिफल देर से प्राप्त होने के कारण निजी क्षेत्र रुचि नहीं लेते।

(d) जनोपयोगी क्षेत्र या सेवाएँ

इस प्रकार स्वतन्त्रता के बाद 1951 में केन्द्रीय उपक्रमों की संख्या 5 थी जो 2011-12 में 249 हो गयी 2007-08 तक केन्द्रीय उपक्रमों में 4,55,409 करोड़ रु० का विनियोग किया गया जिसमें सेवा क्षेत्र में 44.49%, शक्ति (बिजली 27.49%) खनिज में 8.83%, कृषि में 0.04%, शेष 10.55% विनिर्माण क्षेत्र में।

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा आधारभूत उद्योग जैसे शक्ति, कोयला, पेट्रोलियम, भारी उद्योग और इस्पात, खाद, आदि में सार्वजनिक विनियोग किया गया। वित्तीय सेवाओं और व्यावसायिक बैंक, राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी में कुल सार्वजनिक क्षेत्र विनियोग का 82.4%, 2004-05 में किया गया था।